केंद्र ने दिए ₹2801 करोड़, लेकिन किसानों तक नहीं पहुंचे

संजीव बालियान बोले- नई फसल बीमा पॉलिसी जल्द, प्रीमियम भी कम पड़ेगा

कहा, धान और गेहूं की तरह दालों की भी होगी बाजार भाव पर खरीद

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने प्रदेश सरकार पर किसानों को समय से मुआवजा न देने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दैवीय आपदा, बेमौसम बरसात और ओलावृष्टि के चलते किसानों को हुए नुकसान के मुआवजे के लिए केंद्र सरकार ने प्रदेश को 2801 करोड़ रुपये दिए थे। पर, सभी किसानों को अभी तक मुआवजा नहीं मिल पाया है। बालियान शनिवार को लखनऊ में भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 'उन्नत भारत अभियान प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था' पर आयोजित कार्यशाला के उद्घाटन सत्र के बाद पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों के लिए नई फसल बीमा योजना लाने जा रही है। इस पर किसानों को मौजूदा किसी भी बीमा योजना की तुलना में काफी कम प्रीमियम देना होगा। केंद्रीय मंत्री ने दालों का बफर स्टॉक बनाने के लिए गेहूं और धान की तरह इसकी भी सरकारी खरीद शुरू कराने की जानकारी दी। कहा कि एफसीआई और नेफेड के माध्यम से किसानों से दाल खरीदी जाएगी। वह भी बाजार भाव पर। यह भी कहा कि प्रदेश को इस बार 27000 करोड़ रुपये दिए गए हैं। यह पहले की तुलना में काफी ज्यादा है, पर सरकार खर्च नहीं कर रही है।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में शनिवार को 'उन्नत भारत अभियान प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था' पर आयोजित कार्यशाला में मौजूद केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान एवं अन्य।

पैसा नहीं खर्च कर पाए तो दूसरे राज्यों को दे देंगे

बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार कृषि योजनाओं के लिए पूरा बजट खर्च न कर पाने वाली राज्य सरकारों के कोटे में कटौती करने पर विचार कर रही है। सोचा जा रहा है कि जो राज्य कृषि योजनाओं के लिए केंद्र से मिलने वाला पूरा धन खर्च न कर पाएं उनका धन काटकर उन राज्यों को दे दिया जाए जो अच्छा काम कर रहे हैं।

जमीन की कोई कमी नहीं

इस सवाल पर कम होते कृषि क्षेत्र से निपटने के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है। बालियान ने बताया कि बहुत बड़े पैमाने पर अब भी ऐसी जमीन पड़ी है जिसका सुधार करके खेती के कामकाज में लाया जा सकता है। देश में 55 प्रतिशत खेती वर्षा पर आधारित है। इसे सिंचाई सुविधा उपलब्ध करा दी जाए तो पैदावार काफी बढ़ सकती है। केंद्र सरकार ने इसे सिंचित क्षेत्र में बदलने की योजना बनाई है।

सूबे को सूखा राहत के लिए मदद जल्द

पत्रकारों के सवालों पर बालियान ने बताया कि सूखा राहत के लिए भी केंद्र से जल्द ही प्रदेश को धन उपलब्ध करा दिया जाएगा। सूखा की स्थिति का जायजा लेने आई केंद्रीय टीम संभवतः एक सप्ताह में केंद्र सरकार को रिपोर्ट दे देगी। उसके बाद केंद्र सरकार प्रदेश को राहत के लिए पैसा देगी। पर, प्रदेश सरकार से आग्रह है कि पैसा मिलने के बाद वह उसे जल्द से जल्द किसानों को मुहैया करा दे। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार किसानों को होने वाले नुकसान के आकलन के लिए नई पद्धति पर विचार कर रही है। मौजूदा प्रक्रिया में लंबा समय लगता है। इसलिए केंद्र का विचार है कि ड्रोन कैमरा या सैटेलाइट व जीपीएस की मदद से किसानों के नुकसान का आकलन कर लिया जाए।

स्मृति ईरानी व संत कणि सिद्धेश्वर महाराज ने भी संबोधित किया

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये कार्यशाला को संबोधित किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि कार्यशाला के निष्कर्षों को जमीन पर उतारने में केंद्र सरकार के सभी संस्थान सहयोग करेंगे। कनेरी मठ, कोल्हापुर के स्वामी संत कणि सिद्धेश्वर महाराज ने कहा कि उन्नत भारत अभियान में कृषि, आरोग्य, शिक्षा, युवा तथा कुटीर उद्योग पर जोर देकर आदर्श ग्राम विकास के सपने को साकार किया जा सकता है। कार्यशाला में यूपी के अलावा, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड और मध्यप्रदेश के 265 से अधिक कृषि विद्वान एवं प्रयोगधर्मी किसान हिस्सा ले रहे हैं।

राज्य सरकार की ढिलाई से बढ़ रहा वेस्ट यूपी में तनाव

केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने प्रदेश सरकार पर कानून-व्यवस्था पर ढिलाई का आरोप लगाया है। कहा कि सरकार की ढिलाई से पश्चिमी यूपी में तनाव बढ़ रहा है। एक समुदाय के लाखों लोग सड़कों पर उतरकर माहौल खराब कर रहे हैं फिर भी सपा सरकार हाथ पर हाथ रखे बैठी है। सरकार को इस अराजकता पर नियंत्रण लगाना चाहिए। ये बातें उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कहीं। पत्रकारों ने उनसे दो समुदायों के लोगों के सड़क पर उतरने से खराब हो रहे माहौल को लेकर सवाल पूछा था। इस पर उन्होंने कहा कि दो नहीं सिर्फ एक ही समुदाय के लोग माहौल खराब कर रहे हैं। कानून-व्यवस्था प्रदेश सरकार का मामला है। पर प्रदेश सरकार चुपचाप बैठी है। एक समुदाय को ढील से सड़कों पर भीड़ बढ़ती जा रही है। प्रदेश सरकार को कानून-व्यवस्था की स्थिति ठीक रखने के लिए तत्काल कड़े कदम उठाने चाहिए। न उठाए गए तो स्थिति गंभीर हो सकती है। इस सवाल पर कि वेस्ट यूपी की स्थिति ठीक रखने के लिए केंद्र प्रदेश सरकार को कोई सलाह देगी। इस पर उन्होंने कहा कि कई बार एडवाइजरी भेजी जा चुकी है। पर, प्रदेश सरकार अमल नहीं कर रही है।

यूरिया की ₹70,000 करोड़ सब्सिडी सीधे किसानों को

- 'प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था' पर कार्यशाला में बोले केंद्रीय कृषि राज्यमंत्री

अमर उजाला ब्यूरो

लखनऊ। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा कि प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए यूरिया खाद पर प्रतिवर्ष दी जाने वाली 70,000 करोड़ रुपये सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजी जाएगी। इस पर सैद्धांतिक सहमति बन गई है। उम्मीद है, जल्द ही इस पर अमल शुरू कर दिया जाएगा। इससे प्रत्येक किसान के खाते में 5000 रुपये प्रतिवर्ष पहुंच जाएंगे। हालांकि शर्त यह होगी कि वह देशी गाय पाले और यूरिया की जगह खेतों में गोबर का इस्तेमाल करे।

उन्होंने कहा कि परम्परागत, ऑर्गेनिक या प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रत्येक राज्य को दस हजार क्लस्टर बनाने को कहा गया है। एक क्लस्टर 50 हेक्टेयर का होगा। क्लस्टर में शामिल प्रत्येक किसान को केंद्र सरकार तीन वर्ष तक 20,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता मुहैया कराएगी। डॉ. बालियान शनिवार को यहां भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में 'प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था' पर दो दिवसीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र को संबोधित कर रहे थे।

स्टाफ व मशीनें नहीं तो यूपी में कैसे हो रही मिट्टी जांच

डॉ. बालियान ने प्रदेश में मिट्टी जांच अभियान में बड़ी गड़बड़ी की आशंका जताई। कहा कि जब प्रयोगशालाओं में उपकरण और स्टाफ की काफी कमी है तो इतनी जांच रिपोर्ट कैसे बन गई हैं। कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। फर्जी जांच रिपोर्ट बनाई जा रही हैं।

बदलेगा कृषि अध्ययन का पाठ्यक्रम

डॉ. बालियान ने कहा कि कृषि से उच्च शिक्षा पाने वाले विद्यार्थी खेतों पर जाएं और अपने ज्ञान से खेती की सेहत सुधारें, इसके लिए कृषि शिक्षा से जुड़े संस्थाओं का पाठ्यक्रम बदला जाएगा। नए पाठ्यक्रम में एक वर्ष सिर्फ प्रायोगिक खेती का होगा।

किसानों के खाते में सीधे जाएगी खाद सब्सिडी

◆ केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने कहा, पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से मिलेगी सब्सिडी

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में शनिवार को आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में उपस्थित लोगों को संबोधित करते केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री डॉ. संजीव बालियान जागर

राज्य ब्यूरो, लखनऊ : खाद पर दी जाने वाली सब्सिडी सीधे किसानों के खाते में भेजने पर केंद्र सरकार विचार कर रही है। यह राशि औसतन पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर होने की उम्मीद है। शनिवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान परिसर में आयोजित प्राकृतिक खेती एवं गो आधारित अर्थव्यवस्था विषयक कार्यशाला में केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यह जानकारी दी।

उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत आयोजित कार्यशाला में कृषि राज्य मंत्री ने कहा कि खाद पर इस समय 70 हजार करोड़ रुपये सब्सिडी दी जाती है जो उन्होंने केंद्रीय खाद मंत्री अनंत कुमार से सीधे किसानों को देने के मसले पर बात की है। प्रधानमंत्री भी इससे सहमत है। अनुमान है किसानों को प्रति वर्ष पांच हजार रुपये प्रति हेक्टेयर की दर से खाद सब्सिडी मिलेगी। किसान अपनी इच्छानुसार खाद खरीद सकेंगे।

परम्परागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए देश में 50-50 एकड़ के दस हजार क्लस्टर बनाने का फैसला लिया गया है। ऐसे सभी किसानों को केंद्र सरकार अलग से बीस हजार रुपये प्रति हेक्टेयर अनुदान भी देगी। अब सबको समझ में आ गया है कि रासायनिक खेती का रास्ता गलत था। इसी तरह देशी गायों को लेकर भी सक्रियता बढ़ी है। अभियान चल रहे है और दस साल में फिर हर गांव में देशी गाय होगी।

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उपमहानिदेशक डॉ. एनएस राठौड़ ने कहा कि जुलाई 2016 से कृषि शिक्षा का स्वरूप बदल जाएगा। कृषि छात्रों को एक वर्ष जमीनी अनुभव कराए जाएंगे। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. एडी पाठक ने आभार व्यक्त किया।

चूल्हे से बिजली, गोबर से कार

उन्नत भारत अभियान के सलाहकार प्रो. राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि ऐसे चूल्हे विकसित हो गए हैं, जिनसे बिजली बनाई जा सकती है। अभियान के समन्वयक प्रो. वीके विजय ने बताया कि गोवंश संरक्षण से ऊर्जा पर भी आत्मनिर्भर बना जा सकता है। बायोगैस से वह खुद चार साल से कार चला रहे हैं।

रसायनों ने बनाया कामचोर

उन्नत भारत अभियान के संरक्षक हृदय नाथ सिंह ने कहा कि रसायनों ने हमें कामचोर व आलसी बना दिया। खेती व पशुपालन का सीधा रिश्ता है और इस रिश्ते को कमजोर करने से ही खानपान व धरती जहरीली हो गई है। प्राकृतिक कृषि अभियान के समन्वयक गोपाल उपाध्याय ने कहा कि खेती को लाभ का सौदा बनाए बिना स्थितियां नहीं बदलेंगी।

गेहूं का हर दाना जहरीला

महाराष्ट्र के एक गांव को बिना सरकारी मदद के आदर्श गांव में बदलने वाले स्वामी काड सिद्धेश्वर ने कहा कि रासायनिक खेती से गेहूं का हर दाना जहरीला हो गया है। आजादी के समय देश में रासायनिक खादों की खपत महज 540 टन थी, जो अब बढ़ कर 90 हजार टन प्रतिवर्ष है।

केंद्रीय संस्थान उन्नत भारत के साथ

कार्यशाला को स्काइप के माध्यम से संबोधित करते हुए केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा कि उन्नत भारत अभियान से ही देश को सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सकता है। केंद्र के सभी शैक्षिक संस्थान मिलकर इस अभियान के साथ जुड़ेंगे।

अनुदान नहीं दे रही राज्य सरकार

बालियान ने कहा कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ओलावृष्टि प्रभावित किसानों को अनुदान के लिए 2801 करोड़ रुपये दिए थे किन्तु वह अब तक किसानों को नहीं मिले। केंद्र से पिछले वर्षों की तुलना में इस वर्ष 27 हजार करोड़ रुपये अधिक दिये गए। दरअसल प्रदेश सरकार केंद्र से मिले धन का सही इस्तेमाल ही नहीं करती है।

प्रदेश सरकार ने 15 दिन पहले सूखे के लिए मुआवजे का प्रस्ताव भेजा है, उस पर विचार हो रहा है। उन्होंने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ने के लिए भी प्रदेश सरका को कठघरे में खड़ा किया।

किसान बीमा दो माह में

बालियान ने कहा केंद्र सरकार अगले माह के भीतर किसान बीमा योजना ला कर देगी। इसमें प्रीमियम बहुत कम रहेगा ताकि अधिक से अधिक किसान इसका ला उठा सकें।

समृद्धि के लिए जैविक उर्वरक का प्रयोग करें किसान

◆ भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला आयोजित

◆ उन्नतशील और समृद्ध भारत बनाने का संकल्प

जासं, लखनऊ : उन्नत भारत अभियान के तहत शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला शनिवार से शुरू हुई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान परिसर में शुरू हुई कार्यशाला में देशभर से आए वैज्ञानिकों ने किसानों को रासायनिक के बजाय जैविक उर्वरकों का प्रयोग करने की सलाह दी। सभी वैज्ञानिकों ने देश को उन्नत एवं समृद्धशाली बनाने का संकल्प भी लिया।

नई दिल्ली स्थित भारतीय वैज्ञानिक संस्थान के प्रोफेसर वीके विजय ने कहा कि अधिक उत्पादन के लिए जमीन को बंजर बनाने की प्रवृत्ति को रोकनी होगी। किसान जैविक उर्वरकों का प्रयोग करके न केवल भारत को समृद्ध कर सकते हैं, बल्कि जमीन को भी बंजर बनाने से रोक सकते हैं। उन्होंने किसानों को सलाह दी कि अब वह समय नहीं रहा कि परंपरागत खेती करके किसान सभी की भूख मिटा सके। ऐसे में किसानों को एक से अधिक फसल लेने पर विचार करना चाहिए।

वैज्ञानिक राजेंद्र प्रसाद ने उन्नत भारत अभियान के साथ ही विकास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने के लिए किसानों को खेती की तकनीक पर बदलाव पर चर्चा की। उन्होंने कहा कि किसानों को गेहूं, धान और गन्ने के साथ ही दलहनी और तिलहनी खेती की ओर ध्यान देना होगा। वैज्ञानिक सूर्यकांत जलान ने कम पानी में अधिक उत्पादन के लिए बहुफसली खेती करने पर बल दिया। गोपाल उपाध्याय ने कहा कि अन्नदाता किसानों को अधिक मेहनत के बावजूद न तो फसल का उचित दाम मिल पाता है और न ही उन्हें समय से उन्नतशील बीज ही मिल पाता है। इस पर भी सभी को ध्यान देना चाहिए। तकनीकी सत्र में चंद्र प्रकाश, अखिलेश के साथ ही ब्रजेंद्र पाल, महेंद्र मोदी व अजय प्रकाश सहित कई वैज्ञानिकों ने उन्नतशील खेती के बारे में विस्तार से चर्चा की। प्रधान वैज्ञानिक और प्रवक्ता डॉ. एके शाह ने बताया कि रविवार को भी कम पानी में अधिक उत्पादन को लेकर वैज्ञानिक चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय कार्यशाला में कई प्रदेशों से आए 250 से अधिक वैज्ञानिक भाग ले रहे हैं। सोमवार को कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि होंगे।

मठ को बना दिया प्रयोगशाला

राष्ट्रीय कार्यशाला में शामिल हुए कोल्हापुर के कनेरी मठ से आए संत कणिसिद्धेश्वर जी महाराज आकर्षण का केंद्र बने रहे। संत ने जब एक एकड़ खेती में 100 से अधिक फसल लेने की बता कही तो सभी का ध्यान उनके अभिभाषण की ओर चला गया। महाराज ने बताया कि कोल्हापुर में उनके मठ की देखरेख में कृषक सुधार अभियान चलाया जा रहा है। किसानों को परंपरागत खेती के साथ ही साग, सब्जी, दाल-दलहन, अनाज, फल, और फूलों की खेती करने पर भी बल दिया। उन्होंने कहा कि यदि किसान दो गाय पाल ले तो उसकी सभी जरूरतें पूरी हो सकती हैं। उन्होंने बताया कि एक किग्रा गोबर की खाद 10 लीटर पानी को भूमि में संरक्षित करता है। पिछले 10 वर्षों से उनका यह प्रयास अब रंग लाने लगा है। अब महाराष्ट्र के साथ ही बिहार व उत्तर प्रदेश के किसानों से मिलकर इस व्यवस्था को लागू करने का प्रयास करूंगा।

मृदा परीक्षण के लिए जागरूक हों किसान

रासायनिक उर्वरकों के अंधाधुंध प्रयोग से खेतिहर भूमि की उर्वरा शक्ति कम होने लगी है। ऐसे में किसानों को जैविक उर्वरकों के साथ ही मृदा परीक्षण कराने के प्रति जागरूक होना होगा। ऊसर सुधार निगम की ओर से कुर्सी रोड के उमरा में जागरूकता अभियान चलाया गया। निगम के मीडिया प्रबंधक डॉ.केबी त्रिवेदी ने बताया कि निगम के संयुक्त प्रबंध निदेशक डॉ.बीपी सिंह ने मिट्टी की जांच कराने के प्रति किसानों को सजग रहने का आह्वान किया। इस अवसर पर डॉ.सौरभ अरोड़ा व सुरेंद्र सिंह शेखावत समेत कई वैज्ञानिकों और किसानों ने हिस्सा लिया।

लखनऊ और नयी दिल्ली से प्रकाशित

पायनियर

लखनऊ, रविवार, 13 दिसंबर, 2015
पृष्ठ 12+4 मूल्य ₹ 3
लखनऊ संस्करण

भारतीय गन्नना अनुसंधान संस्थान में प्राकृतिक खेती व गौ विकास पर कार्यशाला

वर्तमान कृषि व्यवस्था की जगह परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना आवश्यकः बालियान

पायनियर समाचार सेवा। लखनऊ

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन केंद्रीय राज्यमंत्री डा. संजीव बालियान ने किया। उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुये कहा कि वर्तमान की कृषि व्यवस्था को बदलने की आवश्यकता को बताया तथा कहा कि आज विश्वविद्यालयों में कृषि की सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है जिसे पढ़कर छात्र आगे प्रायौगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें पूरी कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। देशी गाय की महत्ता को समझना होगा तथा सरकार इसकी संख्या बढ़ाने में प्रयासरत है। उम्मीद है कि अगले दस वर्षों में प्रत्येक गाँव में देशी गाय की उपलब्धता होगी तथा शंकर किस्मों की गायें कम हो जाएगी लेकिन हमें देशी गाय की वर्तमान उत्पादकता 4-5 किलो दूध प्रतिदिन से बढ़ाकर 10-15 किलो प्रतिदिन दूध देने वाली करनी होगी। उन्होंने कहा कि जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके। बैल चालित खेती के यंत्र विकसित करने चाहिए तथा किसान भी बैल की संख्या अपने गाँव में बढ़ाएं जिससे खेती के ज्यादातर कार्य के लिए टैक्टर पर निर्भर नहीं होना पड़े। डा. बालियान ने बताया कि आज केन्द्रीय सरकार सलाना 70,000 करोड़ रुपये यूरिया पर सब्सिडी देता है इस सब्सिडी को बंद कर सीधा किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाए तो किसान कार्बनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में कर सकता है। इस अवसर पर सरकारी योजना की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्यों को 10,000 समूह प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य देगा तथा एक समूह में 50 हेक्टेयर भूमि होगी तथा प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की मदद कार्बनिक खेती के लिए दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के द्वारा दिल्ली से कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित किया तथा उन्होंने इस कार्यक्रम की सफ लता के लिए शुभकामना दी। श्रीमती इरानी ने विचार विमर्श उपरान्त उभर कर आने वाले निष्कर्ष पर गहराई से चिन्तन तथा क्रियान्वयन करने पर मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बताया। कनेरी मठ, कोल्हापुर के स्वामी सन्त कणिसिद्धेश्वर जी महाराज विशिष्ठ अतिथि के रूप में संबोधित करते हुए कहा कि मिट्टी में एक किलो गोबर की खाद डालने से मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता 10 लीटर तक बढ़ जाती है। उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत कृषि, आरोग्य, शिक्षा, युवा तथा कुटीर उद्योग पर जोर देते हुए आदर्श ग्राम विकास के सपने को साकार किया जा सकता है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप महानिदेशक (कृषि शिक्षा) डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों के संचालन के लिए परिषद् एक नोडल एजेंसी है। कृषि शिक्षा में आमूल परिवर्तन के लिए परिषद् स्नातक कृषि के लिए नया पाठ्यक्रम बनाने जा रहा है। जिसमें 1 वर्ष सिर्फ प्रायोगिक खेती बतायी जाएगी जिसमें गांवों में प्राकृतिक खेती, उद्यमिता विकास, सामाजिक एवं कृषि परिवेश का अध्ययन विद्यार्थियों द्वारा होगा। उन्होंने कहा कि उद्यमिता विकास पर 405 अनुभवजन्य शिक्षा केन्द्र हैं तथा 105 दक्षता उपकेन्द्र उपलब्ध हैं जहाँ खेती की प्रायोगिक तथा व्यवसायिक जानकारी दी जा सकती है। उन्नत भारत अभियान के संरक्षक हृदय नाथ सिंह ने अपने संबोधन में प्राकृतिक खेती एवं गौशाला विकास के लिए राज्य सरकारों एवं केन्द्र सरकार को आगे आने का अवाहन किया।

लखनऊ, रविवार, 13 दिसम्बर, 2015

परख सच की

जनसंदेश टाइम्स

कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की जरूरत: डॉ. बालियान

लखनऊ। केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री डॉ. संजीव बालियान ने कहा है कि वर्तमान परिवेश में विश्वविद्यालयों में कृषि की सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है जिसे पढ़कर छात्र आगे प्रायोगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें पूरी

कार्यशाला

आइआइएसआर में प्राकृतिक खेती एवं गौ विकास पर कार्यशाला शुरु

कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। देश हित में परम्परागत कृषि को बढ़ावा दिया जाये। केन्द्रीय मंत्री शनिवार से शुरू हुए दो दिवसीय कार्यशाला में उक्त बातें कहीं।

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आइआइएसआर) में प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित दो दिवसीय कार्यशाला का बतौर मुख्य अतिथि के रुप शुभारम्भ करने के बाद केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बैल चालित खेती के यंत्र विकसित करने चाहिए तथा किसान भी बैल की संख्या अपने गांव में बढ़ाएं जिससे खेती के ज्यादातर कार्य के लिए ट्रैक्टर पर निर्भर नहीं होना पड़े। आज केन्द्रीय सरकार सलाना 70 हजार करोड़ रुपये यूरिया पर सब्सिडी देता है इस सब्सिडी को बंद कर सीधा किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाए तो किसान कार्बनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में कर सकता है। केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्यों को 10 हजार समूह प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य देगा तथा एक समूह में 50 हेक्टेयर भूमि होगी तथा प्रति हेक्टेयर 20 हजार रुपये की मदद कार्बनिक खेती के लिए दी जाएगी। केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति ईरानी ने वीडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से दिल्ली से कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित किया। ईरानी ने विचार विमर्श उपरान्त उभर कर आने वाले निष्कर्ष पर गहराई से चिन्तन व क्रियान्वयन करने पर मंत्रालय की प्रतिबद्धता को बताया। उद्घाटन कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप महानिदेशक डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्नत भारत अभियान के अन्तर्गत कृषि कार्यक्रमों के संचालन के लिए परिषद् एक नोडल एजेंसी है। आइआइएसआर के वैज्ञानिक डॉ. एके साह ने बताया कि गन्ना रसायनिक उर्वरक प्रयोग किए बिना सिर्फ जैविक खादों,पदार्थों से उगाया जा सकता है और उत्पादन लागत में बचत के साथ अधिक शुद्ध मुनाफा प्राप्त किया जा सकता है। साथ ही मृदा स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। कार्यशाला का समापन रविवार को संस्थान के प्रेक्षागृह में होगा ,जिसमें कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री राधा मोहन सिंह मुख्य अतिथि के रुप में शामिल होंगे। वसं.

तेलीबाग स्थित गन्ना संस्थान में राष्ट्रीय कार्यशाला उन्नत भारत अभियान कार्यक्रम में उपस्थित राज्य कृषि एवं किसान कल्याण केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान व अन्य

कैनविज टाइम्स 2 रविवार, 13 दिसम्बर 2015

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में दो दिवसीय कार्यशाला शुरू

परंपरागत कृषि को बढ़ावा देना जरूरी : डॉ. बालियान

कैनविज टाइम्स ब्यूरो

लखनऊ। वर्तमान की कृषि व्यवस्था को बदलना होगा। क्योंकि विश्वविद्यालयों में कृषि की सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, जिसे पढ़कर छात्र प्रायोगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है। उन्होंने देशी गाय का महत्व बताते हुए कहा कि सरकार इनकी संख्या बढ़ाने का प्रयास कर रही है। आने वाले दस वर्षों में सभी गांवों में देशी गाय उपलब्ध होगी और शंकर किस्मों की गाय कम हो जाएंगी। यह विचार केन्द्रीय कृषि एवं किसान मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान ने भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान की कार्यशाला में व्यक्त किये।

डॉ. बालियान ने शनिवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में आयोजित प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषयक दो दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करते हुए डॉ. बालियान ने कहा कि पूरी कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है।

कार्यक्रम

- वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुई स्मृति ईरानी

डॉ. बालियान ने कहा कि केन्द्र सरकार हर साल 70,000 करोड़ रुपये यूरिया पर सब्सिडी देती है। उन्होंने कहा कि इस सब्सिडी को बंद कर सीधा किसानों को 5000 रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाएगा। जिससे किसान कार्बनिक खादों का प्रयोग अपने खेतों में कर सकता है। सरकारी योजना की जानकारी देते हुए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री ने बताया कि केन्द्र सरकार प्रत्येक राज्यों को प्रतिवर्ष10 हजार समूह बनाने का लक्ष्य देगा। एक समूह में 50 हेक्टेयर भूमि होगी। प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपये की मदद कार्बनिक खेती के लिए दी जाएगी। विशिष्ट अतिथि कनेरी मठ कोल्हापुर के स्वामी संत कणिसद्धेवर महाराज ने कहा कि मिट्टी में एक किलो गोबर की खाद डालने से मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता 10 लीटर तक बढ़ जाती है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप महानिदेाक (कृषि शिक्षा) डा. नरेन्द्र सिंह राठौड़ ने की। संस्थान में प्रेस व मीडिया अध्यक्ष डॉ. एके साह ने कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, हरियाणा, पंजाब, सिक्किम, बिहार, उत्तराखंड, झारखंड, मध्यप्रदेश के 265 से अधिक कृषि विद्वान एवं प्रयोगधर्मी किसान भाग ले रहे हैं।

शनिवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में समारोह में केंद्रीय मंत्री डॉ. संजीव कुमार बालियान कनेरी मठ कोल्हापुर के स्वामी संत कणिसद्धेवर महाराज। कैनविज टाइम्स

वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के जरिये शामिल हुई स्मृति ईरानी

मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के द्वारा दिल्ली से कार्यशाला में भाग ले रहे प्रतिभागियों को संबोधित किया। उन्होंने कार्यक्रम की सफलता के लिए शुभकामना दी। उन्होंने कहा कि किसानों के लिए मंत्रालय प्रतिबद्ध है।

किसानों तक नहीं पहुंचे मुआवजे के 2,801 करोड़ : बालियान

लखनऊ | राजीव शुक्ल

किसानों को मुआवजा देने के लिए केन्द्र द्वारा दिए गए 2801 करोड़ रुपये अभी तक बांटे नहीं गए हैं। मिट्टी जांच की फर्जी रिपोर्ट किसानों को दी जा रही है। उन्नत भारत अभियान में शनिवार को शरीक होने आए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री संजीव बालियान ने कहा कि केन्द्र द्वारा भेजे गए पैसे की जांच कराई जानी चाहिए।

केन्द्र ने पैसा दिया लेकिन किसानों को नहीं मिल रहा मुआवजा : श्री बालियान ने प्रदेश सरकार को जमकर आड़े हाथ लिया। उन्होंने कहा कि सूखा और बारिश से परेशान किसानों को मुआवजा देने के लिए केन्द्र ने 2801 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए हैं लेकिन सरकार इसका ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रही। बोले - जहां का मैं रहने वाला हूं वहां के किसानों को अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। मुआवजे के लिए सरकार को और पैसा उपलब्ध कराने के सवाल पर उन्होंने कहा कि केंद्रीय टीम अभी जांच करके आ गई है। उसकी रिपोर्ट के आधार पर मुआवजा राशि बढ़ाने पर विचार किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बड़े किसानों को भी दो हेक्टेयर में हुए नुकसान का मुआवजा दिया जाएगा।

केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान

देसी गाय को बढ़ावा देने के लिए मिशन 'गोकुल'

उन्होंने कहा कि हम तो विदेशी गाय को ही समझते थे कि ज्यादा दूध देती है लेकिन हमें ब्राजील ने बताया कि देसी गाय भी ज्यादा दूध दे सकती है। समस्या यह है कि साहीवाल जैसी देसी गाय मिल ही नही पाती। केन्द्र सरकार ने 500 रुपए से मिशन गोकुल के तहत देसी गाय की संख्या बढ़ाने के लिए एनडीआरआई करनाल और मेरठ में रिसर्च सेंटर शुरू किया है। हमारा लक्ष्य अगले दस वर्ष में हर गांव में 15 से 20 लीटर दूध देने वाली देसी गाय उपलब्ध कराना है।

किसानों का बीमा प्रीमियम कम होगा

किसानों का कम नुकसान हो इसके लिए टेक्नोलॉजी उपलब्ध कराई जाएगी। इस पॉयलट प्रोजेक्ट के लिए सरकार ने 300 करोड़ रुपये जारी किए हैं। वही किसानों के लिए जारी बीमा योजना में प्रीमियम भी कम किया जाएगा।

प्रदेश सरकार दे रही मिट्टी की फर्जी जांच रिपोर्ट : केन्द्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा कि प्रदेश सरकार मिट्टी की जो जांच रिपोर्ट किसानों को दे रही है वह फर्जी है। सरकार के पास न तो कर्मचारी और न संसाधन। यहां तक की मिट्टी जांच करने के लिए केमिकल तक नहीं हैं।

दाल की भी खरीद करेगी केन्द्र सरकार : श्री बालियान ने कहा कि दाल की खेती को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार ने एफसीआई से दाल भी खरीदने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए सरकार 500 करोड़ रुपये खर्च करके बफर स्टाक बनाएगी। जिससे दालों के दामों पर अंकुश लगाए जा सकें। दाल की जमाखोरी पर उन्होंने प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया। बोले- जिन प्रदेश सरकारों ने दाल के जमाखोरों पर अंकुश लगाया वहां दाल के दाम नहीं बढ़े।

देसी गाय पालन के साथ प्राकृतिक खेती पर जोर

गन्ना अनुसंधान संस्थान में शनिवार को दो दिवसीय सेमिनार शुरू हुआ।

राष्ट्रीय सहारा
www.samaylive.com
सच कहने की हिम्मत
राष्ट्रीयता • कर्त्तव्य • समर्पण
...रादून • वाराणसी से प्रकाशित
लखनऊ। रविवार • 13 दिसम्बर • 2015

ग्रामीण क्षेत्रों में हों कृषि शोध संस्थान

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के सभागार में दीप जलाकर कार्यशाला का उद्घाटन करते केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री संजीव बालयान। फोटो : एसएनबी

लखनऊ (एसएनबी)। रायबरेली रोड स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के सभागार में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के तत्वावधान में उन्नत भारत अभियान के तहत दो दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। इसमें प्राकृतिक कृषि एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर बल दिया गया। कार्यक्रम में केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री संजीव बालयान ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि के दीप प्रज्वलन के साथ हुई। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के निदेशक प्रो. एडी पाठक द्वारा मुख्य अतिथि को पुष्प गुच्छ, स्मृति चिह्न व अंग वस्त्र भेंट किया। कार्यक्रम में आये वक्ताओं व अतिथियों ने प्राकृतिक कृषि एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर प्रकाश डाला।

■ कार्यशाला में प्राकृतिक कृषि व गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर बल

मुख्य अतिथि ने अपने संबोधन में कहा कि उन्नत भारत अभियान की शुरुआत आईआईटी दिल्ली से हुई है जिसे हमें मूर्त रूप देना है। देश की पूर्व सरकारों ने जिन कार्यो को गावों से शुरू करना था उनको शहरों में समेट कर रख दिया। हमारे देश में कृषि शोध संस्थानों को शहरों में बसाया जबकि इनकी आवश्कता ग्रामीण क्षेत्रों को है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में है जिसके 150 किमी की परिधि में गन्ने की पैदावार ही नही है। हमारे कृषि वैज्ञानिक शहरों के वातानुकूलित कक्षों में शोध किया करते है, जिसने गांव खेत देखा ही नहीं है आखिर वह कृषि वैज्ञानिक कैसे हो सकते है? सही मायने में कृषि वैज्ञानिक ही खेतों में काम करते है और वही मूर्त रूप देते हैं। आज हमारे कृषि आधारित पढाई करने वाले छात्रों की सोच पढाई कर एक अच्छी नौकरी प्राप्त कर शहरों में बसना होता है न कि पढाई पूरी कर ग्रामीण क्षेत्रो में जाकर कृषि को बढावा देना। एक किलो गेंहू में 27 से 28 मिलीग्राम ऐसे तत्व पाए गये हैं जो हमारे शरीर के लिये जहर का काम करते हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हमें जैविक खेती पर विशेष बल देना होगा जिसके लिये हमें गाय, बैल व भैस आदि जानवरों को पलना होगा जिससे हमें रासायनिक

कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव जरूरी: संजीव बालियान

डेली न्यूज नेटवर्क

- प्रति हेक्टेयर कार्बन खेती के लिए 20 हजार रुपए की मदद देगी केंद्र सरकार
- मानव संसाधन मंत्री स्मृति इरानी ने वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए किया संबोधन
- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्राकृतिक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर हुआ कार्यक्रम

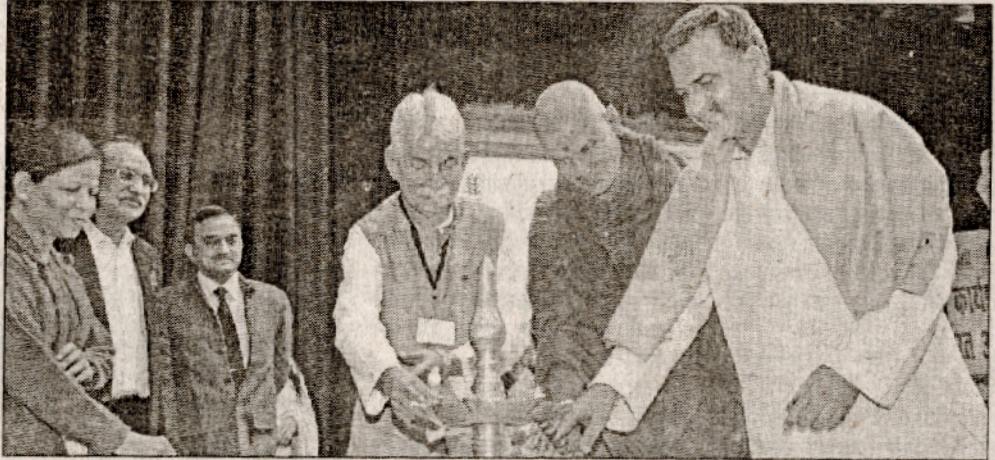

लखनऊ। मौजूदा समय में विश्वविद्यालयों में कृषि की सैद्धांतिक शिक्षा दी जाती है, जिसे पढ़कर छात्र आगे प्रायौगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है। इसलिए हमें पूरी कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। देशी गाय की महत्ता को समझना होगा और सरकार इसकी संख्या बढ़ाने में कोशिश कर रही है। उम्मीद है कि अगले दस वर्षों में हरेक गांव में देशी गाय की उपलब्धता होगी। यह बात कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री,भारत सरकार के डॉ. संजीव कुमार बालियान ने कही। वह शनिवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान (आईआईएसआर) में प्राकृतिक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे।

उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सलाना 70,000 करोड़ रूपए यूरिया पर सब्सिडी देता है। इस सब्सिडी को बंद कर सीधा किसानों को 5000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से दिया जाए, तो किसान कार्बनिक खादों का इस्तेमाल अपने खेतों में कर सकते हैं। डॉ. बालियान ने बताया कि केंद्र सरकार हरेक राज्य को 10,000 समूह प्रतिवर्ष बनाने का लक्ष्य देगा। साथ ही एक समूह में 50 हेक्टेयर भूमि होगी और प्रति हेक्टेयर 20,000 रुपए की मदद कार्बनिक खेती के लिए दी जाएगी। मानव संसाधन विकास मंत्री स्मृति इरानी ने वीडियो कान्फ्रेंसिंग के तहत संबोधित करते हुए कहा कि विचार विमर्श के बाद आने वाले नतीजों पर गहराई से चिंतन और क्रियान्वयन करने पर मंत्रालय की प्रतिबद्धता रहेगी। कनेरी मठ, कोल्हापुर के स्वामी संत कणिसिद्धेश्वर जी महाराज ने कहा कि मिट्टी में एक किलो गोबर की खाद डालने से मिट्टी की जल संरक्षण क्षमता 10 लीटर तक बढ़ जाती है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के उप महानिदेशक डॉ. नरेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि उन्नत भारत अभियान के तहत कृषि कार्यक्रमों के संचालन के लिए परिषद् एक नोडल एजेंसी है। इस मौके पर उन्नत भारत अभियान के संरक्षक हृदय नाथ सिंह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली के प्रोफेसर वीके. विजय, आईआईएसआर के प्रेस व मीडिया अध्यक्ष डॉ. एके. साह के अलावा अन्य ने भी अपनी बात रखी।

प्रभात
लखनऊ। रविवार, 13 दिसम्बर 2015

खेती से गोपालन जोड़कर ही होगा कृषि का विकास : बालियान

प्राकृतिक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर हो रही चर्चा

- भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था में आयोजित उन्नत भारत अभियान कार्यशाला शुरू
- दो दिनों तक चलेगी कार्यशाला
- केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री ने किया उद्घाटन

लखनऊ। प्रभात

भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्था लखनऊ में शनिवार को दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला की शुरुआत हुई। उन्नत भारत अभियान कार्यशाला में प्राकृतिक खेती और गौ आधारित अर्थव्यवस्था विषय पर चर्चा हुई। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री संजीव बालियान ने दीप प्रज्ज्वलित कर इसका उद्घाटन किया।

इस दौरान उन्होंने कहा, ''गोपालन और कृषि एक साथ करने से ही किसानों का जीवन संवरेगा। वजह, किसान गांवों में रहता है और यहीं से विकास शुरू होता है। गांवों के छोटे किसानों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए भी योजनाएं बनीं हैं।''

उन्होंने कहा, ''गोपालन से किसानों के खेती की लागत कम आएगी। जमीन में कीटनाशकों का प्रभाव भी कम होगा। छोटे किसानों को खेती करने में आसानी होगी। उर्वरकों का बोझ कम होगा। देसी नस्ल की गायों को पालकर किसान अपनी स्थिति सुधार सकेंगें।''

उन्होंने कहा, ''छोटे किसानों को ध्यान में रखकर सरकार ने बैल आधारित यंत्रों के निर्माण और शोध की ओर ध्यान केंद्रित किया है। अगर बैल से चलने वाले बिजली यंत्र, सिंचाई के लिए ज़मीन से पानी निकालने वाले यंत्र आदि का निर्माण हो जाए तो गांवों में खुशियां आ जाएंगीं। किसानों के चेहरों से गायब हो चुकी खुशी वापस लौट आएगी।''

इस मौके पर भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान के महानिदेशक एनएस राठौर, निदेशक एडी पाठक, स्वामी सिद्धेश्वर जी महाराज, राजेंद्र प्रसाद, प्रो. वीके विजय, हृदयनाथ सिंह, गोपाल, डॉ एके शाह, डॉ. आईएस अनवर आदि उपस्थित रहे।

स्वतंत्र भारत

नहीं खाने दूंगा किसी को जहर, कृषि को उद्यम से जोड़कर करूंगा देश का विकास : संजीव

लखनऊ (सं.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री संजीव बालियान ने कृषि में बढते केमिकल एग्रीकल्चर के पैटर्न को रोकने और लोगों को आर्गेनिक खेती के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से पूरे यूपी से राजधानी आये किसानों के सामने प्रण किया कि जब तक उनकी सरकार है वह किसी को केमिकल एग्रीकल्चर से पैदा हुए अनाज रूपी जहर को नहीं खाने देंगे। उन्होंने कहा कि एक किलोग्राम अनाज में 27 से 28 मिलीग्राम पेस्टिसाइड है। यह सबके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है इसे कम करना होगा। अब हम अपने लोगो को जहर नहीं खिला सकते। उन्होंने किसानों से अपील की कि वह प्राकृतिक खेती अपनायें और उसे उद्यम से जोडें। इससे उन्हें ही फायदा होगा और उनकी प्रगति होगी। ऐसे कौशल विकास से ही भारत आगे बढ़ पायेगा। उक्त बातें उन्होंने राजधानी स्थित भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में उन्नत भारत अभियान के तहत प्राकृतिक खेती एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था पर आयोजित राष्ट्रीय कार्यशाला में कहीं।

कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम में उद्यमिता से जुड़े विषय भी होंगे शामिल : राज्यमंत्री संजीव बालियान ने कहा कि कृषि शिक्षा पाठ्यक्रम को रिवाइज किया जायेगा। अब कृषि की पढ़ाइ के साथ छात्रों को उद्यमिता से जुडे विषय भी पढ़ाए जायेंगे। उनके कौशल विकास से ही गांवों को विकसित किया जा सकता है। जब तक कृषि की पढ़ाई करने वाला युवा कौशल विकास नहीं जानेंगा, तब तक गांवों में खुशी नहीं लौटेंगी। गाय और गोवंश पर आधारित शिक्षा को भी बढ़ावा देने का काम होगा। बैल आधारित यंत्रों के विकास के क्षेत्र मे भी सरकार ने काम करना शुरू कर दिया है। छात्रों को इसके बारे में भी जानकारी दी जायेगी।

बढ़ेगी कृषि वैज्ञानिकों की संख्या, कम लागत वाले कृषि यंत्रों को लाने की तैयारी : केंद्रीय राज्यमंत्री संजीव बालियान ने कहा कि हमारा प्रयास है कि कुछ भी करके देश में कृषि वैज्ञानिकों की संख्या में इजाफा और कम लागत वाले यंत्र तैयार करने की कोशिशें तेज की जायें। इनमें पानी निकालने वाले यंत्र, बिजली पैदा करने के लिए बैल से चलाए जाने वाले यंत्र कचरे को खाद के रूप में परिवर्तित करने के लिए बैल चालित यंत्रों के निर्माण पर फोकस होगा। ऐसा करने के पीछे पर्यावरण प्रदूषण को रोकना और खेती की लागत को कम करना है। इसके अलावा किसानों को भी ट्रैक्टर जैसे आधुनिक यत्र की महंगाई से बचाया जाएगा और उन्हें सस्ते कृषि यंत्रों को उपलब्ध कराया जाएगा।

गिर और साहीवाल गायों का बढ़ेगा महत्व : उन्नत भारत अभियान के सलाहकार प्रोफेसर राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि इस प्रोग्राम के तहत गिर और साहीवाल जैसी देसी गायों से अधिक दूध लेने का काम भी होगा। हम केवल विदेशी नस्ल की गायों के भरोसे नहीं रह सकते है। यह दुख की बात है कि यह हम तब जान पाए हैं, जब ब्राजील ने हमें यह बताया है कि भारतीय नस्ल की गिर और साहीवाल से भी अधिक दूध लिया जा सकता है।

किसानो के लिये यूपी में बनाया जायेगा क्लस्टर : केंद्रीय मंत्री बालियान ने यूपी में किसानों का क्लस्टर बनाने की बात भी कहीं। उन्होंने बताया कि प्रत्येक क्लस्टर 50 एकड़ का होगा। इनमें कई किसान शामिल होंगे। फर्टिलाइजर में मिलने वाली सब्सिडी किसानों के खाते में भेजी जाएगी। यह सब्सिडी 5 हजार रुपए प्रति हेक्टर के हिसाब से दी जाएगी। अगले 10 साल में हर गांव में देसी गाय और गोवंश उपलब्ध कराने का प्रयास चल रहा है। देश के किसानों में 85 प्रतिशत छोटी जोत वाले किसान हैं। इन्हें सस्ता यत्र उपलब्ध कराया जाएगा। खेती को लाभकारी बनाने के लिए ऐसे शोध जरूरी हैं, जिनका लाभ सीधे तौर पर छोटे किसानों को मिलें।

मिट्टी की जांच पर बालियान ने उठाये यूपी के संसाधनों पर सवाल : केंद्रीय राज्य मंत्री बालियान ने यूपी की मिटटी जांच कराने की कवायद पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी की मिट्टी जांच फर्जी है। न स्टाफ है न ही लैब में केमिकल हैं, फिर जांच कैसे हो रही है। ऐसा करके प्रदेश सरकार किसानों के भविष्य व देश दोनों के साथ खिलवाड़ कर रही है। केंद्र सरकार ऐसा नहीं होने देगी। हर किसान को मिटटी जांचने की किट देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनायेंगी।

हिन्दुस्तान, लखनऊ, 13 दिसम्बर 2015

लखनऊ | **कार्यालय संवाददाता**

देसी गाय के पालन को बढ़ावा देने के साथ प्राकृतिक खेती करने पर वक्ताओं ने जोर दिया। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में उन्नत भारत अभियान के तहत सेमिनार में विशेषज्ञों ने विचार रखे। शनिवार को इस दो दिवसीय सेमिनार का उद्घाटन केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री संजीव बालियान ने किया।

उन्नत भारत अभियान के समन्वयक प्रो. वीके विजय ने कहा कि खेती कैसे हो, पर्यावरण कैसा हो, स्वच्छता कैसे हो इनके लिए यह कार्यक्रम उपयोगी होने जा रहा है। क्योंकि ग्रामीण ऊर्जा, जल संसाधन और कारीगर के लिए उद्योग जैसी व्यवस्था के बारे में आपके विचार आमंत्रित हैं।

एक देसी गाय से तीस एकड़ प्राकृतिक खेती संभव : समन्वयक गोपाल उपाध्याय ने कहा कि एक देसी गाय का पालन किया जाए तो 10 से 30 एकड़ जमीन पर प्राकृतिक खेती की जा सकती है। ऐसे में गाय के लिए न गोशाला की जरूरत रहेगी और न ही गोरक्षा के लिए आन्दोलन की। हमारे यहां का किसान खेती पर ही निर्भर है। उसे खाद, बीज, कीटनाशक जैसी चीजों के लिए अनेक झंझावतों से गुजरता है। ऐसे में एक गाय का पालन इन सभी जरूरतों को पूरा कर सकती है।

कृषि विवि में शुरू होगा उद्यमिता कार्यक्रम कोर्स

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के उप महानिदेशक डॉ. एन.एस. राठौड़ ने सेमिनार में कहा कि अगले वर्ष 2016 से उन्नत भारत अभियान पर काम शुरू होगा। इसके तहत विश्वविद्यालय में छात्रों को व्यवहारिक शिक्षा देने के लिए उद्यमिता विकास कार्यक्रम की शुरुआत करेगी। इसमें करीब 40 कृषि विवि शामिल किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि इस कोर्स में छात्र दो महीने किसानों के बीच जागरूकता कार्यक्रम चलाएंगे, तैयार सामान को मार्केट में बेचना, दो महीने स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम चलाया जाएगा। विवि में लगभग 105 सेक्टरों पर काम चल रहा है। सेमिनार को हृदयनाथ सिंह, स्वामी सिद्धेश्वरजी आदि ने संबोधित किया।

18 प्रदेशों से कृषि विशेषज्ञों ने की शिरकत

गुजरात, झारखण्ड, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, हिमाचल, कर्नाटक, सिक्किम, महाराष्ट्र, राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखण्ड और उत्तर प्रदेश समेत 18 प्रदेशों के प्रतिनिधियों ने इस सेमिनार में भाग ले रहे हैं।

SUNDAY HINDUSTAN TIMES, LUCKNOW
DECEMBER 13, 2015

Modi govt may rework agri syllabus: Baliyan

HT Correspondent
lkoreportersdesk@hindustantimes.com

LUCKNOW: The Modi government is planning to re-work the country's agriculture studies syllabus, besides toying with the idea of diverting agriculture funds from 'non-performing states to performing ones.'

No decision has been taken on both these aspects but union minister of state for agriculture and food processing Sanjeev Baliyan said at a function at the Sugarcane Research Institute on Sunday that his ministry was seriously considering these proposals. Baliyan's comments came a day before union agriculture minister Radha Mohan Singh is scheduled to visit the state capital on Sunday. Like Baliyan, Singh too would be here to attend the "Unnat Bharat Abhiyan", which is part of the centre's initiative to promote model villages. The UP government, too, has a similar scheme going.

Baliyan, an MP from UP's Muzaffarnagar, said that his ministry would encourage formation of 'clusters of farmers' in UP. "These clusters can come up in a 50 acre of land and the subsidy, let's say the Rs 5000 fertiliser subsidy can then be transferred directly to such farmers," he added. He said, "We need to rework the agri-syllabus as it is being felt that those who have studied agriculture and are known as agri-scientists hardly visit the fields with their learning and the farmer on the fields hardly has any time to learn and mix modern and advanced methods of farming in his daily work. This mismatch has to end and we want to redraft the agriculture syllabus."

Laying stress on conservation of cow and cow products, he hinted this would be a part of the agri syllabus. He spoke of his ministry's thrust on promoting indigenous and local methods to improve agriculture. "The idea is to promote local learning and help the farmers have a say in policy making along with pushing for a modern approach to agriculture. My ministry wishes to encourage rearing of cows with higher milk yield in every village in 10 years' time," he said.

आज

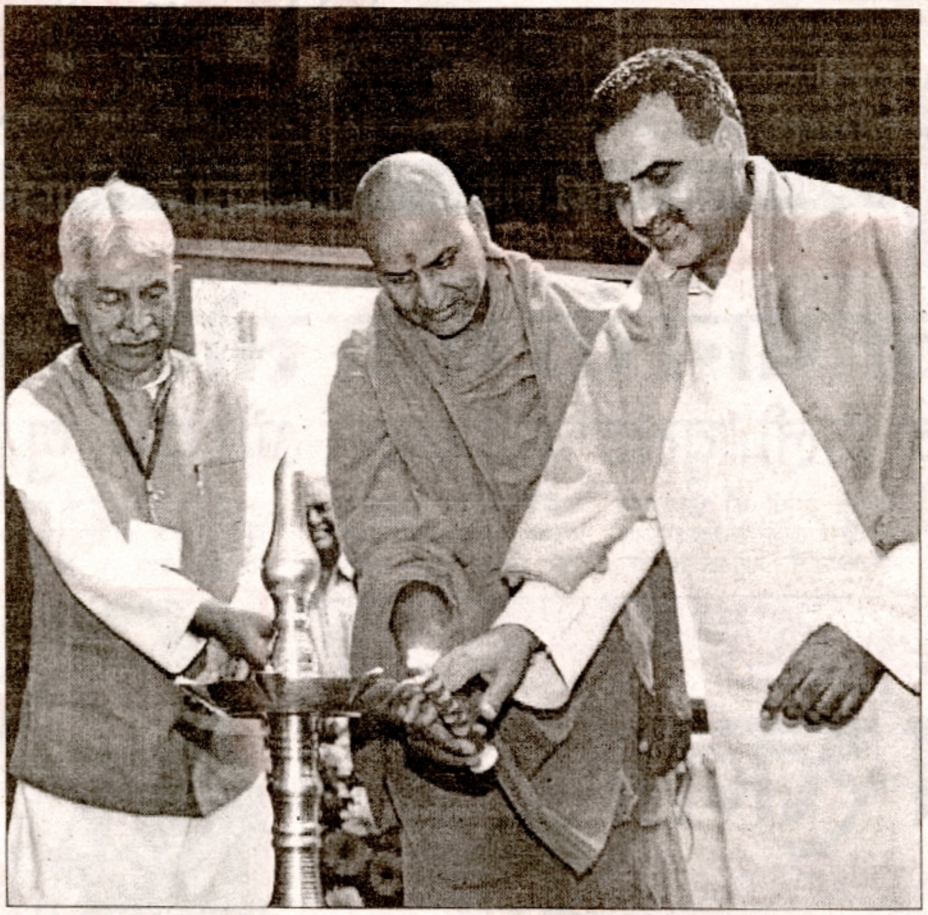

गन्ना अनुसंधान संस्थान में उन्नत भारत अभियान में प्रकृतिक, कृषि एवं गौ आधारित अर्थव्यवस्था कार्यशाला का दीप जला कर शुभारम्भ करते केन्द्रीय मंत्री संजीव वालिया। छाया : आज

नहीं सुधरी ट्रेनों की चाल यात्रियों ने किया हंगामा

लखनऊ, शनिवार। कोहरे के कहर से ट्रेनों की बिगड़ी चाल अभी भी जारी है। यह बात दीगर है कि शनिवार को ट्रेनों के लेटलतीफी की संख्या जरूर कम हुई। इसके बावजूद 188 ट्रेनें 18 घंटे तक लेट रहीं। सवा 11 बजे आने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस दोपहर एक बजे के बाद आकर गई। श्रमशक्ति भी ढाई घंटे विलंब से आई। 6452 यात्रियों ने टिकट लौटायें, जबकि कनेक्टिंग आरक्षण की वजह से 1098 यात्रियों को दूसरी ट्रेनों में जाने की छूट दी गई। इसकी वजह से सुबह से लेकर देरशाम तक प्लेटफार्मों पर यात्रियों का मेला लगा रहा। कोई इंक्वायरी काउंटर की लाइन में लगा दिखा तो कोई वेटिंग हाल में। ट्रेनों की लेटलतीफी से जहां इंतजाम पूरी तरह से धराशायी हुए वहीं वेंडरों और कुलियों ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ट्रेनों के प्लेटफार्म बदलने से कुली मनचाहा पैसा लेकर उन्हें दूसरी जगह पहुंचा रहे थे। चाय छह के स्थान पर दस तो छोला-भटूरा बीस के बजाय तीस रुपए प्लेट बिका। आईआरसीटीसी के फूड प्लाजा में भी संचालक भीड़ का फायदा उठाने से नहीं चूके।

रसायन मुक्त खेती से कृषक और खेत दोनों होंगे सुदृढ़

(आज समाचार सेवा)

लखनऊ, शनिवार। रायबरेली दिलकुशा संस्थान में दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला उन्नत भारत अभियान आज से शुरू हो गया। इस कार्यशाला में देश के तमाम जनपदों से आये सैकड़ों किसानों ने भाग लिया। इस कार्यक्रम में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती के बारे में बताया गया। रसायनमुक्त खेती से कृषक और खेत दोनों सुदृढ़ होंगे। दो दिवसीय कार्यशाला में प्राकृतिक खेती जल संरक्षण हेतु पारम्परिक खेती वानिकी गौसंवर्धन, पंचगव्य उत्पाद एवं बायोगैस ऊर्जा के विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई, एवं देश के विभिन्न राज्यों से इस क्षेत्रों के विद्वान, प्रोफेसर विषय वस्तु विशेषज्ञ, एन.जी.ओ. के प्रतिनिधियों ने भाग लिया तथा अपने-अपने विचार व्यक्त किये। इस कार्यक्रम में तीन तकनीकी सत्रों में प्रस्तावित विषयों पर प्रस्तुती एवं गहन विचार विमर्श कर प्राकृतिक खेती एवं गौशाला विकास के लिए आवश्यक दिशा निर्देश किसानों को दिया गया। कार्यक्रम में

•उन्नत भारत अभियान कार्यशाला शुरू

उपस्थित आईपीएस महेन्द्र मोदी ने बताया कि आज इस तरह की बीमारियां फैल रही है जिसका मुख्य कारण है, कैमिकल रहित खेती और प्राकृतिक खेती किसान करें तो उन्हें किसी प्रकार की बीमारियों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसके लिए गौशाला खोलना महत्वपूर्ण हैं, गौ मूत्र का गोबर का प्रयोग जहां खेती के लिए उपयोगी हैं।

YOUNG INDIA > YOUNG PAPER

NBT

संडे नवभारत टाइम्स

22 शक 1937 > मार्गशीर्ष शुक्ल 2 विक्रम 2072 | नई दिल्ली/ लखनऊ > रविवार, 13 दिसंबर 2015 [26*> | मूल्य सिर्फ 3.50 रु.

मिट्टी जांच की फर्जी रिपोर्ट दे रहा यूपी

लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री बालियान ने लगाया आरोप

■ वरिष्ठ संवाददाता, लखनऊ

कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने किया वर्कशॉप का उद्घाटन।

कृषि राज्य मंत्री संजीव बालियान ने यूपी सरकार पर आरोप लगाया है कि किसानों को मिट्टी जांच की फर्जी रिपोर्ट सौंपी जा रही है। उन्होंने कहा कि मिट्टी जांच कर किसानों को हेल्थ कार्ड देने की योजना शुरू की गई है। लेकिन यूपी सरकार के पास लैब है न स्टॉफ। ऐसे में प्रदेश के अधिकारी किसानों को फर्जी रिपोर्ट दे रहे हैं। वे शनिवार को भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान में प्राकृतिक खेती और गो आधारित अर्थव्यवस्था पर शनिवार को शुरू हुए दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के उद्घाटन सत्र में शामिल होने राजधानी पहुंचे थे।

उन्होंने कहा कि किसानों के लिए नई बीमा पॉलिसी लाई जा रही है जिसमें उन्हें काफी कम प्रीमियम देना होगा। एक सवाल पर बालियान ने बताया कि दालों का बफर स्टॉक बनाया जाएगा। इसके लिए एफसीआई और नैफड जैसी संस्थाएं दाल की खरीद करेंगी।

देशी गाय के लिए अनुदान देगी केंद्र सरकार

शी गाय और परंपरागत कृषि को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार विशेष अनुदान देगी। ऑर्गेनिक खेती के लिए केंद्र हर राज्य में 10 हजार समूह प्रतिवर्ष बनाएगा। एक समूह में 50 हेक्टेयर कृषि भूमि शामिल होगी। बालियान ने कहा कि इसके अलावा सरकार देसी गायों की संख्या बढ़ाने में प्रयासरत हैं। उम्मीद है कि अगले दस वर्षों में हर गांव में देशी गाय की उपलब्धता होगी और संकर किस्मों की गायें कम हो जाएंगी। इसके लिए देशी गाय की उत्पादकता 4-5 किलो दूध प्रतिदिन से बढ़ाकर 10-15 किलो प्रतिदिन दूध देने वाली करनी होगी, जिससे किसानों को अच्छा मुनाफा प्राप्त हो सके।

मंत्री ने कृषि की पढ़ाई को व्यवहारिक बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि विवि में जो पढ़ाया जाता है उसे पढ़कर छात्र आगे प्रायोगिक या प्राकृतिक खेती करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें पूरी कृषि शिक्षा व्यवस्था में बदलाव करने की जरूरत है। कृषि वैज्ञानिक लैब से बाहर निकल खेत में जाते ही नहीं है।

किसानों तक नहीं पहुंचे केंद्र से मिले 2801 करोड़

बालियान ने कहा कि आपदा के लिए केंद्र ने यूपी को 2801 करोड़ दिए लेकिन वह किसानों तक पहुंचे ही नहीं। सूखा प्रभावित जिलों का भी निरीक्षण केंद्रीय टीम कर चुकी है। एक सप्ताह में रिपोर्ट मिल जाएगी। इसके बाद मुआवजा जारी कर दिया जाएगा। केंद्र इस कवायद में है कि सेटेलाइट या जीपीएस के जरिए ऐसी तकनीक विकसित की जाए कि नुकसान का आकलन जल्दी और प्रभावी ढंग से किया जा सके। बालियान ने कहा कि जो राज्य केंद्र का पैसा नहीं खर्च कर पाएंगे। उनका बजट काट पर बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों को आवंटित कर दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने विडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कार्यशाला को संबोधित किया। कनेरी मठ, कोल्हापुर के कणिसिद्धेश्वर जी महाराज, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के डिप्टी डॉयरेक्टर नरेंद्र सिंह राठौड़ सहित दूसरे वक्ताओं ने भी संबोधित किया। कार्यशाला का समापन रविवार को होगा जिसमें केंद्रीय कृषि मंत्री राधामोहन सिंह मौजूद रहेंगे।